

एस. पी. गोयल और जे. वी. गुप्ता से पहले, जे.जे., के सामने

आयकर आयुक्त, -आवेदक।

बनाम

जगाधरी इलेक्ट्रिक सप्लाय एंड इंडस्ट्रियल कंपनी-प्रतिवादी।

1975 का आयकर संदर्भ संख्या 66 और 67

17 मार्च 1981.

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII)-धारा 184(7), 185(3), 253(1) (सी) और 263-आयकर नियम 1962-नियम 24 धारा 184 के तहत पंजीकृत फर्म की निरंतरता के बारे में घोषणा फर्म ने अपने संविधान में कोई बदलाव किए बिना अगले वर्ष में दायर किया - घोषणा स्वीकार की गई और पंजीकरण जारी रखने की अनुमति दी गई - आयकर अधिकारी - क्या यह कहा जा सकता है कि उसने धारा 263 (1) के अर्थ के भीतर 'आदेश' पारित किया है - आदेश पारित किया गया है धारा 263 (1) के तहत आयुक्त ने अपील में निर्धारिती ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश को बरकरार रखने को चुनौती दी, लेकिन विभिन्न आधारों पर- ट्रिब्यूनल के पास ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र है या नहीं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 184 (7) और 263 (1) के प्रावधानों और आयकर नियम, 1962 के नियम 24 को पढ़ने से यह माना गया कि एक फर्म के पंजीकरण को जारी रखने से संबंधित है अगले वर्ष, यह नहीं कहा जा सकता कि पंजीकरण जारी रखने का मामला अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं है। यदि यह अधिनियम के तहत कार्यवाही है तो इसके तहत पारित कोई भी आदेश अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत कवर किया जाएगा। आयकर अधिकारी को इस प्रश्न पर अपना दिमाग लगाना होगा कि क्या निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत घोषणा अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप है या नहीं और खुद को संतुष्ट करने के बाद, अनुदान की प्रकृति के संबंध में आवश्यक आदेश दें। एक प्रमाणपत्र का रिकार्ड किया जाना है। भले ही इसे औपचारिक आदेश माना जाए लेकिन फिर भी इसे रिकार्ड करना जरूरी है। कुछ आदेश और ऐसा आदेश, जब आयकर अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा, अधिनियम के तहत कार्यवाही में होगा और अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत कवर किया जाएगा; बशर्ते अन्य शर्तें भी पूरी हों। एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। यदि इस प्रकार

पारित आदेश या आयकर अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र एसओ ऐसी प्रकृति का है कि गलत होने पर, राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो अधिनियम की धारा 263 (1) के प्रावधान आकर्षित होंगे। दूसरे शब्दों में, यह आदेश की प्रकृति है जो अधिनियम की धारा 263 की प्रयोज्यता का निर्धारण करेगी। (पैरा 9)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

(1981) 2

यह माना गया कि अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत आयुक्त में निहित क्षेत्राधिकार एक विशेष प्रकृति का है या, दूसरे शब्दों में, आयुक्त के पास आयकर अधिकारी के आदेश को संशोधित करने के लिए अधिनियम के तहत विशेष क्षेत्राधिकार है यदि वह मानता है कि उसके द्वारा पारित कोई भी आदेश पूर्वाग्रह की हद तक गलत था! राजस्व के हितों के लिए. ऐसा करने से पहले, उसे निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देना भी आवश्यक है। यदि अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत उसके द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में निर्धारिती को सुनने के बाद, वह संतुष्ट नहीं है, तो वह आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। बेशक, इस प्रकार पारित आदेश में आयकर अधिकारी के आदेश को गलत मानने का आधार शामिल होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत विचार किया गया है। इससे व्यथित महसूस करते हुए, निर्धारिती अधिनियम की धारा 253 (1) (सी) के तहत प्रावधान के अनुसार इसके खिलाफ अपील दायर कर सकता है। अपील के ज्ञापन में, निर्धारिती से आयुक्त के आदेश पर हमला करने और उसके आदेश में दिए गए निर्णय के आधार को चुनौती देने की अपेक्षा की जाती है। सुनवाई के समय, यदि निर्धारिती ट्रिब्यूनल को संतुष्ट कर सकता है कि आयुक्त द्वारा आदेश में दिए गए निर्णय के आधार तथ्यों पर गलत हैं या कानून में मान्य नहीं हैं, तो ट्रिब्यूनल के पास अपील स्वीकार करने और निर्धारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आयुक्त के आदेश को दरकिनार कर दिया. ट्रिब्यूनल किसी अन्य आधार पर आयुक्त के आदेश को बरकरार नहीं रख सकता है, जो उसकी राय में आयुक्त के लिए भी उपलब्ध था। यदि ट्रिब्यूनल को अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत आदेश पारित करने के लिए आयुक्त के पास उपलब्ध आधारों का पता लगाने की अनुमति दी जाती है, तो यह आयुक्त में निहित विशेष क्षेत्राधिकार को साझा करने के समान होगा जो कि इसके तहत जरूरी नहीं है। कार्यवाही करना। यह और भी अधिक है, क्योंकि राजस्व को अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील का कोई

अधिकार नहीं दिया गया है। यदि वह उसके द्वारा दिए गए नोटिस के अनुसरण में निर्धारिती को सुनने के बाद आगे बढ़ता है, तो अधिनियम की धारा 253 (1) (सी) के तहत निर्धारिती द्वारा दायर अपील को आदेश के खिलाफ अपील के समान नहीं माना जा सकता है। अपीलीय सहायक आयुक्त की मूल्यांकन कार्यवाही में पारित जहां दोनों पक्षों को अपील का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत आयुक्त द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्धारिती द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते समय ट्रिब्यूनल उन आधारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है जिन्हें आयुक्त ने स्वयं अपने आदेश का आधार बनाना उचित नहीं समझा।

(पैरा 13)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256 (1) के तहत संदर्भ में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (चंडीगढ़ बेंच) चंडीगढ़ I.T.A 1972-73 का 1318 आर.ए. संख्या 73 और 76 1974-1975 के लिए मूल्यांकन वर्ष 1966-67 के अहम सवाल के लिए कानून बनाया गया ।

- (i) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इसे रद्द करना कानूनन उचित था इस मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उनके पास भेजने के बजाय अतिरिक्त आयुक्त का आदेश क्या है ?

आयकर आयुक्त बनाम जगाधरी इलेक्ट्रिक सप्लाय एंड इंडस्ट्रियल कंपनी (जे. वी. गुप्ता, जे.)

- (ii) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण यह मानने में सही था कि पंजीकरण के विवादित प्रमाण पत्र को दर्ज करने में आयकर अधिकारी की कार्रवाई को गलत नहीं कहा जा सकता है 25 अक्टूबर, 1964 को साझेदारी के साधन में दर्शाए गए अनुपात से भिन्न अनुपात में निर्धारिती फर्म द्वारा हानि का वितरण?
- (iii) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण सही था, यह मानने में कि मौजूदा मामले में, धारा 263 के तहत क्षेत्राधिकार का कोई प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि आय अनुभाग के अर्थ में कर अधिकारी द्वारा कोई आदेश नहीं था ।

(iv) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल वयस्क भागीदारों की संख्या 10 से 11 तक बढ़ने के तथ्य पर विचार करने में सक्षम नहीं था, भले ही अतिरिक्त आयुक्त ने फॉर्म (छह) में इस पर भरोसा नहीं किया था उक्त परिवर्तन पर आयकर अधिकारी का आदेश ग़लत हो गया?

डी.एन.अवस्थी, एडवोकेट बी.के. झिंगन एडवोकेट याचिकाकर्ताओं के साथ

जी. सी. शर्मा, अधिवक्ता, अशोक भान, डी.के. गुप्ता और ई.डी. हेल्म्स, प्रतिवादियों के वकील.

फैसला

जे. वी. गुप्ता, जे.

(1) ये दो संदर्भ, संख्या 66 और 67, 1975, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, (इसके बाद ट्रिब्यूनल कहा जाएगा) के 3 सितंबर, 1974 के एक आदेश से उत्पन्न हुए, धारा 256 के तहत किए गए हैं (1) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, दोनों पक्षों यानी कर दाता और राजस्व दोनों के कहने पर। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश, दिनांक 17 जून, 1975 के माध्यम से, इस न्यायालय की राय के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्नों को संदर्भित किया है:

(i) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उन के पास भेजने के बजाय अतिरिक्त आयुक्त के आदेश को रद्द करना कानून न उचित था?

आई.एल.आर.

पंजाब

और

हरियाणा

(1981) 2

(ii) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, 25 अक्टूबर, 1964 को साझेदारी के साधन में दर्शाए गए अनुपात से भिन्न अनुपात में निर्धारिती फर्म द्वारा हानि का वितरण में न्यायाधिकरण यह मानने में कानूनन सही था

कि पंजीकरण के विवादित प्रमाण पत्र को दर्ज करने में आयकर अधिकारी की कार्रवाई को गलत नहीं कहा जा सकता है?

- (iii) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर; न्यायाधिकरण, कानून के अनुसार, सही था कि मौजूदा मामले में, धारा 263 के तहत क्षेत्राधिकार का कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा के अर्थ में आयकर अधिकारी द्वारा कोई आदेश नहीं था?
- (iv) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल वयस्क भागीदारों की संख्या 10 से 11 तक बढ़ने के तथ्य पर विचार करने में सक्षम नहीं था, भले ही अतिरिक्त आयुक्त ने फॉर्म (छह) में इस पर भरोसा नहीं किया था उक्त परिवर्तन पर आयकर अधिकारी के आदेश को गलत बताया गया है?

इसके बाद, इस न्यायालय ने, 1976 के आयकर मामले संख्या 43 और 44 में, दिनांक जुलाई, 1980 के आदेश के तहत, उपरोक्त प्रश्न संख्या (i) को हटाने का निर्देश दिया और ट्रिब्यूनल को आगे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले का पूरक बयान. नतीजतन, ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश, दिनांक 19 सितंबर, 1980 के तहत, इस न्यायालय की राय के लिए कानून के निम्नलिखित पूरक प्रश्नों को संदर्भित किया है?

- (1) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, निर्धारिती ने अपनी विस्तृत लिखित आपत्तियां प्रस्तुत की थीं और उसे अपने साथी के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई भी दी गई थी और धारा 263(1) के स्पष्ट प्रावधान आयकर अधिनियम; क्या अपीलीय न्यायाधिकरण का यह मानना सहीथा कि सुनवाई को स्थगन न देकर अतिरिक्त आयकर आयुक्त द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है?
- (2) यदि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सकारात्मक है; क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा रिमांड न देना कानूनन उचित था

निर्धारिती को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद मामले को नए सिरे से तय करने के लिए आयुक्त को या ऐसे अन्य निर्देश के साथ जो वह देना उचित समझे?

2. इन सन्दर्भों को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य ये हैं। निर्धारिती फर्म का गठन 25 अक्टूबर, 1964 के साझेदारी दस्तावेज के अनुसार किया गया था। उस समय, साझेदारी के लाभों के लिए 10 वयस्क साझेदार और चार नाबालिगों को अनुमति दी गई थी। उक्त चार नाबालिगों में से, एक, अर्थात्, घनशाम गुप्ता, ने 25 अप्रैल, 1965 को, यानी प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान, वयस्कता प्राप्त की और उन्होंने 25 अक्टूबर, 1965 तक, अपने संबंध को समाप्त करने की कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी। भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1952 की धारा 30(5) के तहत अपेक्षित साझेदारी के साथ। साझेदारी विलेख के खंड (6) में अन्य बातों के साथ-साथ फर्म के मुनाफे में दस वयस्क साझेदारों के संबंधित शेयरों और चार नाबालिगों के शेयरों के लिए प्रावधान किया गया है। कंपनियों के मुनाफे में। उक्त खंड में आगे प्रावधान किया गया है कि हानि की स्थिति में, इसे दस वयस्क भागीदारों द्वारा उनके संबंधित शेयरों के आलोक में विभाजित किया जाना था।

3. निर्धारण वर्ष 1966-67 के लिए, निर्धारिती फर्म ने 4 अक्टूबर, 1967 को अपनी आय का रिटर्न निर्धारित फॉर्म संख्या 12 में घोषणा के साथ दाखिल किया, जैसा कि आयकर नियम, 1962 के नियम 24 के तहत माना गया है। इसके बाद इसे नियम कहा जाएगा) इस आशय का कि फर्म के गठन या साझेदारों के शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा कि 25 अक्टूबर, 1964 के साझेदारी विलेख से प्रमाणित है, जिसके आधार पर पहले के लिए पंजीकरण किया गया था। मूल्यांकन वर्ष प्रदान किया गया था। 20 दिसंबर, 1978 को आयकर अधिकारी द्वारा मूल्यांकन पूरा होने से पहले, फर्म ने अधिनियम की धारा 139(4) के तहत, 3 सितंबर, 1970 को एक संशोधित रिटर्न प्रस्तुत किया। दो गतिविधियों पर, एक बिजली आपूर्ति उपक्रम के माध्यम से और दूसरा इंजीनियरिंग कार्यों के माध्यम से। पहली गतिविधि पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के पक्ष में बिजली उपक्रम की बिक्री के परिणामस्वरूप 13 नवंबर, 1965 को समाप्त हो गई। उक्त गतिविधि से, निर्धारिती के खाते की किताबों के अनुसार, फर्म ने रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। 35,337 रुपये के वैधानिक रिजर्व से अधिक। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 57 के तहत 29,738 बनाया गया। इंजीनियरिंग अक्टूबर 1965 में ही

शुरू हुई कार्य गतिविधि का परिणाम नेट हो गया था रुपये का नुकसान 52,187. इस उपक्रम की बिक्री के परिणामस्वरूप

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(1981)2

रुपये की रसीद 13,72,402, और बिक्री पर विचार के माध्यम से एक और दावा अभी भी लंबित है। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत संशोधित रिटर्न अन्य बातों के साथ-साथ एक संशोधित लाभ और हानि और विनियोग खाते के साथ था, जैसा कि 31 मार्च, 1966 को था, जिसमें रुपये की गैर-हानि का वितरण दिखाया गया था। ग्यारह साझेदारों के बीच 7,482 रु. उनमें से कथित घनशाम गुप्ता वह थे जो 25 अक्टूबर, 1965 को साझेदारी के कानून के तहत भागीदार बने थे, जैसा कि ऊपर बताया गया है। उक्त संशोधित खाते में उसका घाटा 3-3/4 प्रतिशत हिस्से पर निकाला गया। आयकर अधिकारी ने निर्धारिती के पहले पंजीकरण को मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रभावी माना, और 'भाग' शब्द की परिभाषा के अनुसार सभी 14 भागीदारों (नाबालिगों सहित) को शेयर आय आवंटित की। अधिनियम की धारा 2(23) में), 25 अक्टूबर 1964 के साझेदारी विलेख के खंड (6) के अनुपात के अनुसार तहत प्रदान किए गए।

4. अतिरिक्त आयकर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत कार्यवाही शुरू की, और, अपने आदेश, दिनांक 13 अक्टूबर, 1972 द्वारा, यह माना कि मूल्यांकन वर्ष 1965-66 के लिए निर्धारिती को पंजीकरण प्रदान किया गया था। मूल्यांकन वर्ष 1966-67 के लिए इसका प्रभाव नहीं होना था, क्योंकि यह देखा गया था कि "चूंकि किताबों में अपनाया गया शेयर आवंटन वास्तव में साझेदारी विलेख में उल्लिखित से अलग था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वास्तविक व्यवहार में फर्म, साझेदारी के साधन में उल्लिखित से अलग था। इसलिए, धारा 184(7) के तहत दायर घोषणा में दिया गया प्रमाणपत्र गलत था। फर्म का संविधान बदल गया था और किसी भी मामले में भागीदारों के शेयर किताबों के अनुसार थे साझेदारी के विलेख में उल्लिखित के समान नहीं थे। इन परिस्थितियों में, फर्म पंजीकरण के लाभ की हकदार नहीं थी। आईटीओ ने गलती से पंजीकरण की अनुमति दे दी है। चूंकि फर्म कानूनी रूप से पंजीकरण

की हकदार नहीं है, इसलिए उसके नवीनीकरण की अनुमति दी गई है 1.टी.ओ. द्वारा इसके द्वारा रद्द किया जाता है।" अतिरिक्त आयकर आयुक्त के उक्त आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, निर्धारिती ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अधिनियम की धारा 263 (1) (सी) के तहत अपील दायर की।

5. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश, दिनांक 3 सितंबर, 1971 द्वारा आयोजित किया कि आयकर अधिकारी की कार्यवाही आक्षेपित प्रमाण-पत्र को रिकार्ड करने में- पंजीकरण प्रमाणपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता निर्धारिती द्वारा हानि के वितरण का अनुपात भिन्न है जैसा कि 25 अक्टूबर 1964 के साझेदारी विलेख में दर्शाया गया है। निर्धारिती का दूसरा तर्क यह है कि पंजीकरण पहले ही हो चुका है यदि फर्म को धारा 184(7) के तहत जारी रखने की अनुमति दी जाती है

आयकर आयुक्त बनाम जगाधरी इलेक्ट्रिक सप्लाय एंड इंडस्ट्रियल कंपनी (जे. वी. गुप्ता, जे.)

निर्धारण वर्ष 1966-67 में धारा 263(1) के अर्थ में कोई आदेश नहीं था, इसे भी स्वीकार कर लिया गया और यह माना गया कि अधिनियम की धारा 263 के अर्थ में कोई आदेश मौजूद नहीं था जिसे अतिरिक्त आयुक्त द्वारा संशोधित किया जा सकता था। आयकर। इन निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, निर्धारिती की अपील ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार कर ली गई और 13 अक्टूबर, 1972 के अतिरिक्त आयकर आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया गया। हालाँकि, अपने आदेश में, ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि "वर्तमान मामले में, 25 अक्टूबर, 1965 से, फर्म के संविधान में एक स्पष्ट बदलाव हुआ है, यहाँ तक कि 10 साझेदारों और 4 नाबालिगों के स्थान पर भी प्रवेश किया गया है।" (साझेदारी के?) लाभों के लिए, उस तारीख से हमारे पास 11 साझेदारों और तीन नाबालिगों को साझेदारी के लाभों के लिए स्वीकार किया गया है। इस प्रकार आयकर अधिकारी की कार्रवाई, आय की धारा 185 (4) के तहत रिकॉर्डिंग में- कर अधिनियम, इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि फर्म को मूल्यांकन वर्ष 1966-67 के लिए पंजीकृत किया गया है, हमारी राय में, उसकी ओर से एक स्पष्ट त्रुटि है। हम तदनुसार पाते हैं, "इन परिस्थितियों में, यह था कि दोनों पार्टियों, यानी निर्धारिती और राजस्व ने, इस न्यायालय से राय के लिए ट्रिब्यूनल के उक्त आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्नों पर संदर्भ मांगा।

6. प्रश्न संख्या 1 (पूरक-मूल प्रश्न संख्या (i) को हटाने के बाद) के संबंध में, निर्धारिती के विद्वान वकील श्री जी.सी. शर्मा ने शुरुआत में ही स्वीकार कर लिया कि इसका फैसला पक्ष में होगा। राजस्व का और निर्धारिती के विरुद्ध। इस रियायत के मद्देनजर, हम तदनुसार उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं।

7. उपरोक्त प्रश्न संख्या 1 के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न संख्या 2 (पूरक) अस्तित्व में नहीं है और इसलिए, तदनुसार उत्तर दिया गया है।

प्रश्न संख्या (ii) (मूल) :

8. ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर राजस्व की ओर से कोई सार्थक आपत्ति नहीं उठाई जा सकी कि पंजीकरण के विवादित प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड करने में आयकर अधिकारी की कार्रवाई को नुकसान के वितरण के कारण गलत नहीं कहा जा सकता है। 25 अक्टूबर, 1964 के साझेदारी विलेख में दर्शाए गए अनुपात से भिन्न अनुपात में निर्धारिती फर्म। इस फर्म को ध्यान में रखते हुए राजस्व के विरुद्ध और निर्धारिती के पक्ष में ट्रिब्यूनल द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से इस प्रश्न का उत्तर मिलता है ।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा
(1981)2

प्रश्न संख्या (iii) (मूल) :

9. राजस्व के विद्वान वकील के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने यह मानने में गलती की है कि अधिनियम की धारा 263 (1) के अर्थ में आयकर अधिकारी का कोई आदेश मौजूद नहीं था, जिसे अतिरिक्त द्वारा संशोधित किया जा सकता था। आयुक्त, आयकर. उन्होंने अधिनियम की धारा 185 (3) के साथ-साथ नियमों के नियम 22 से 25 का भी उल्लेख किया जो एक फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया और एक फर्म के पंजीकरण को जारी रखने की घोषणा से संबंधित है। उन्होंने इस संबंध में आयकर अधिकारी द्वारा पारित 20 अक्टूबर, 1970 के आदेश का भी उल्लेख किया, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:

“रिटर्न के साथ धारा 184(7) के तहत घोषणा दाखिल की गई है। इस पर सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। यह क्रम में है। चूंकि भागीदारों के रूप में फर्म के संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इस फर्म को पंजीकरण पहले ही दिया जा चुका है। आकलन वर्ष 1966-67 के लिए जारी है।”

दूसरी ओर, निर्धारिती के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह आयकर अधिकारी द्वारा पारित एक स्वतंत्र आदेश नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 184(7) के तहत ऐसे किसी आदेश पर विचार नहीं किया गया है और इसके तहत केवल प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। आयकर अधिकारी ने वर्ष 1966-67 के लिए मूल्यांकन करते समय इसे केवल एक तथ्य के रूप में उल्लेख किया है और इन परिस्थितियों में, इसे अधिनियम की धारा 263 के प्रावधानों को आकर्षित करने वाला आदेश नहीं माना जा सकता है। (1972) (1), अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने राम लाल किशोर लाल बनाम आयकर आयुक्त यू.पी. का भी उल्लेख किया।

अधिनियम की धारा 263(1) में लिखा है, -

“आयुक्त इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग कर सकता है और उसकी जांच कर सकता है; और यदि वह मानता है कि आयकर अधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश गलत है, जहां तक यह राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है, तो वह कर सकता है, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद मूल्यांकन को बढ़ाने या संशोधित करने और मामले की परिस्थितियों के अनुसार उस पर ऐसा आदेश देने या करवाने के बाद, मूल्यांकन को रद्द करने और नए मूल्यांकन का निर्देश देने सहित उचित ठहराना।”

(1) (1972) 84 आई.टी.आर. 138.

आयकर आयुक्त बनाम जगाधरी इलेक्ट्रिक सप्लाय एंड इंडस्ट्रियल कंपनी (जे. वी. गुप्ता, जे.)

अधिनियम की धारा 184(7) में प्रावधान है, -

“जहां किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए किसी फर्म को पंजीकरण प्रदान किया जाता है, यह प्रत्येक अगले वर्ष के लिए प्रभावी होगा:

उसे उपलब्ध कराया:-

- (i) फर्म के गठन या साझेदारों के शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है जैसा कि साझेदारी के दस्तावेज से पता चलता है जिसके आधार पर पंजीकरण दिया गया था; और
- (ii) फर्म, धारा 139 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत अनुमत समय की समाप्ति से पहले (चाहे मूल रूप से तय हो या विस्तार पर) ऐसे बाद के लिए आय की रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत करती है। निर्धारण वर्ष, इस आशय की एक घोषणा, निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से सत्यापित की जाती है, हालांकि, जहां आयकर अधिकारी संतुष्ट है कि फर्म को समय के भीतर घोषणा प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था इतनी अनुमति होने पर, वह फर्म को मूल्यांकन किए जाने से पहले किसी भी समय घोषणा प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।”

नियम 24 यदि नियम इस प्रकार है:-

“धारा 184 की उप-धारा (7) के तहत प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा फॉर्म संख्या 12 में होगी और उसमें बताए गए तरीके से सत्यापित की जाएगी और नियम 22 के उप-नियम (5) के अनुसार संबंधित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।”

किसी फर्म के पंजीकरण को अगले वर्षों में जारी रखने से संबंधित प्रावधानों को पढ़ने से यह नहीं कहा जा सकता है कि पंजीकरण जारी रखने का मामला अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं है। यदि यह अधिनियम के तहत कार्यवाही है, तो इसके तहत पारित कोई भी आदेश अधिनियम की धारा 263(1) के तहत कवर किया जाएगा। यह तर्क कि यह कोई आदेश नहीं है, किसी भी मिसाल से समर्थित नहीं है। रामलाल के मामले (सुप्रा) की वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है। उक्त मामले में, का नोट

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

(1981) 2

कर अधिकारी के अनुसार, "जुर्माना हटा दिया गया" केवल रिकॉर्ड पूरा करने के उद्देश्य से माना गया था और इसे अधिनियम की धारा 263(1) के अर्थ के तहत एक आदेश के रूप में नहीं माना गया था। उपरोक्त मामले में इस संबंध में प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

"जुर्माना लगाना पूरी तरह से निरीक्षण करने वाले सहायक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, और जब उन्होंने आदेश दिया जो उन्होंने किया, तो करने के लिए और कुछ नहीं था। आयकर अधिकारी बाद के आदेश की सीमा या विस्तार नहीं कर सकता था निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश। जब उन्होंने 3 अक्टूबर, 1963 को प्रविष्टि की, तो यह केवल उनके सामने रिकॉर्ड को पूरा करने के उद्देश्य से था। इसके बाद, उन्होंने निर्धारिती को पत्र लिखकर सूचित किया कि दंड की कार्यवाही शुरू हो गई है हटा दिया गया। जब उसने ऐसा किया तो ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कानून ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था, बल्कि इसलिए कि यह सही था कि निर्धारिती को पता होना चाहिए कि कार्यवाही में क्या हुआ था, खासकर धारा 271 के तहत कार्यवाही शुरू होने के बाद (1) (सी) निर्धारिती को किसी भी अवसर पर निरीक्षण सहायक आयुक्त के समक्ष कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। हम अपने मन में स्पष्ट हैं कि 3 अक्टूबर 1963 को आदेश पत्र में आयकर अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टि नहीं की जा सकती उसके द्वारा दिए गए आदेश के रूप में समझा गया। यह अधिनियम की धारा 263(1) के अर्थ के तहत एक आदेश नहीं था और इसलिए, आयुक्त के पास उस प्रावधान के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।"

वर्तमान मामले में, ट्रिब्यूनल धारा 184(7) के तहत प्रदान किए गए अधिनियम पर जो विचार करता है उससे प्रभावित हुआ है। इसके अनुसार, यह पंजीकरण देने जैसी बात नहीं है क्योंकि आयकर अधिकारी ने निर्धारिती की स्थिति का निर्धारण नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 263 के तहत पुनरीक्षण योग्य आदेश पारित किया जा सके। हमारी राय में ट्रिब्यूनल का यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। आयकर अधिकारी को इस प्रश्न पर अपना दिमाग लगाना होगा कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत घोषणा अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार है या नहीं, और खुद को संतुष्ट करने के बाद, प्रकृति में आवश्यक आदेश दें प्रमाणपत्र प्रदान करने का

विवरण दर्ज किया जाना है। भले ही इसे एक औपचारिक आदेश माना जाए, लेकिन फिर भी, कुछ आदेश को रिकॉर्ड करना आवश्यक है, जैसा कि वास्तव में वर्तमान मामले में आयकर अधिकारी द्वारा किया गया है और

आयकर आयुक्त बनाम जगाधरी इलेक्ट्रिक सप्लाय एंड इंडस्ट्रियल कंपनी (जे. वी. गुप्ता, जे.)

जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। ऐसा आदेश, जब आयकर अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा, अधिनियम के तहत कार्यवाही में होगा, और अधिनियम की धारा 263(1) के तहत कवर किया जाएगा; बशर्ते अन्य शर्तें भी पूरी हों। एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। यदि इस प्रकार पारित आदेश या आयकर अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ऐसी प्रकृति का है कि गलत होने पर, राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो अधिनियम की धारा 263(1) के प्रावधान आकर्षित होंगे। दूसरे शब्दों में, यह आदेश की प्रकृति है जो अधिनियम की धारा 263 की प्रयोज्यता का निर्धारण करेगी। वर्तमान मामले में, इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि यदि आयकर अधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र को गलत माना जाता है, तो इससे राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अर्थात् राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध मामले के इस दृष्टिकोण में इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है।

प्रश्न संख्या (iv) (मूल):

10. निर्धारिती के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अतिरिक्त आयकर आयुक्त ने पंजीकृत फर्म को जारी रखने का प्रमाण पत्र देने वाले आयकर अधिकारी के आदेश को इस आधार पर गलत पाया कि फर्म का संविधान बदल गया था और किसी भी मामले में, निर्धारिती की पुस्तकों के अनुसार, भागीदारों के शेयर, 25 अक्टूबर, 1964 के साझेदारी विलेख में उल्लिखित समान नहीं थे। निर्धारिती की ओर से दायर अपील में, ट्रिब्यूनल ने पाया कि यह निष्कर्ष - अपर आयकर आयुक्त का बयान तर्कसंगत नहीं था। और इस प्रकार, इसने अपील स्वीकार कर ली और अतिरिक्त आयकर आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन साथ ही, यह देखने में गलती हुई कि वर्तमान मामले में, 25 अक्टूबर, 1965 से, एक फर्म के गठन में स्पष्ट परिवर्तन यह हुआ कि 10 साझेदारों और 4 नाबालिगों के स्थान पर साझेदारी के लाभों को स्वीकार किया गया, 11 साझेदारों और

3 नाबालिगों को साझेदारी के लाभ के लिए स्वीकार किया गया। विद्वान वकील के अनुसार, ट्रिब्यूनल अतिरिक्त आयुक्त के आदेश को बरकरार रखने और आयकर अधिकारी के आदेश को गलत ठहराने के लिए अपने स्वयं के कारणों को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं था क्योंकि उसके समक्ष अपील की विषय-वस्तु यह थी कि क्या की धारा 263(1) के तहत अतिरिक्त आयकर आयुक्त का आदेश अधिनियम, इस प्रकार वैध था या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि एक बार कारण आयकर के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिए गए माना जाता है

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

(1981) 2

तर्क संगत नहीं, तो मामला खत्म हो गया. अपील के तहत उक्त आदेश को किसी अन्य आधार का आविष्कार करके उचित नहीं ठहराया जा सकता है जो अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत अतिरिक्त आयकर आयुक्त के आदेश का आधार कभी नहीं बना। तर्क यह है कि, अपील में, ट्रिब्यूनल धारा 263 (1) के तहत अतिरिक्त आयकर आयुक्त के आदेश को बरकरार रखने के लिए अपने स्वयं के कारणों को प्रतिस्थापित नहीं कर सका क्योंकि यह न्यायक्षेत्र के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगा। अतिरिक्त आयकर आयुक्त, जो अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत पारित होने वाले आदेश के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है, आयकर आयुक्त का विशेष क्षेत्राधिकार है और उनकी संतुष्टि ही इसका आधार है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि आयकर अधिकारी द्वारा पारित आदेश गलत है क्योंकि यह राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल है। कोई भी अन्य विचार जो अधिनियम की धारा 263(1) के तहत आदेश पारित करते समय आयुक्त के साथ मेल नहीं खाता था, उसे आयुक्त के आदेश में नहीं पढ़ा जा सकता था ताकि दायर की गई अपील में ट्रिब्यूनल द्वारा बरकरार रखा जा सके। निर्धारिती की ओर से. विद्वान वकील के अनुसार, यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि अधिनियम की धारा 253(1) (सी) के तहत, केवल निर्धारिती ही है जो अधिनियम और राजस्व की धारा 263 के तहत आयुक्त द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। अधिनियम की धारा 263 के तहत आयुक्त के आदेश के खिलाफ ऐसी कोई अपील दायर करने के लिए कानून के तहत उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया है, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आयकर

अधिकारी का आदेश गलत नहीं है, जिससे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। राजस्व का आगे यह तर्क दिया गया कि मूल्यांकन कार्यवाही में अपील में अपीलीय सहायक आयुक्तों द्वारा पारित आदेश अलग-अलग स्तर पर हैं क्योंकि उन मामलों में, दोनों पक्षों, यानी निर्धारिती के साथ-साथ राजस्व को भी दायर करने का अधिकार है। न्यायाधिकरण के समक्ष अपील. अपने तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने जे.के. बैंकर्स बनाम आयकर आयुक्त, यू.पी. पर भरोसा जताया। और दूसरा, (2), आर. एल. राजघरिया बनाम आयकर अधिकारी और अन्य (3), आयकर आयुक्त, तमिलनाडु-I बनाम मद्रास इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (4), जौहरी लाल (एच.यू.एफ.) बनाम आयकर आयुक्त, उ.प्र. (5) और आयकर आयुक्त बनाम आर.के. मेटल वर्क्स (6)।

- (2) (1974) 94 1.टी.आर. 107.
- (3) (1977) 107 आई.टी.आर. 347.
- (4) (1980) 124 आई.टी.आर. 454.
- (5) (1973) 88 आई.टी.आर. 439.
- (6) (1978) 112 आई.टी.आर. 445.

आयकर आयुक्त बनाम जगाधरी इलेक्ट्रिक सप्लाय एंड इंडस्ट्रियल कंपनी (जे. वी. गुप्ता, जे.)

11. दूसरी ओर, राजस्व के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिए गए विषय-वस्तु के अलावा अन्य आधार पर अतिरिक्त आयकर आयुक्त के आदेश को बनाए रखने में सक्षम था। अपील में अपर आयुक्त के आदेश की वैधता या अमान्यता थी। किसी भी मामले में, चूंकि ट्रिब्यूनल ने अपील में पूरे मामले को जब्त कर लिया था, इसलिए वह इसमें उचित समझे जाने वाले किसी भी आदेश को पारित करने में सक्षम था। यदि ट्रिब्यूनल द्वारा आयकर अधिकारी के आदेश में अवैधता का पता चला, तो उसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि अतिरिक्त आयुक्त इसे नोटिस करने में विफल रहे। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त आयुक्त द्वारा 13 अक्टूबर 1972 के अपने आदेश में अधूरी अभिव्यक्ति, अपील में इसे ठीक करने के लिए ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगी, हालांकि यह निर्धारिती की ओर से दायर की गई थी। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने मद्रास इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के मामले

(सुप्रा), भगत श्याम एंड कंपनी बनाम आयकर आयुक्त, कैप्रेट, (7), आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल-द्वितीय बनाम इलेक्ट्रो हाउस (8), आयकर आयुक्त, नई दिल्ली (केंद्रीय) बनाम एडवर्ड केवेंटर, (उत्तराधिकारी) पी. लिमिटेड (9), स्टील कंटेनर्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल -II, कलकत्ता (10) और आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल बनाम मेसर्स अमरेन्द्रनाथ मुखर्जी और भाई (11) पर भरोसा किया।

12. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और बार में उद्धृत मामले के कानून का भी अध्ययन किया है। ऊपर उल्लिखित कोई भी मामला सीधे तौर पर इन संदर्भों में निर्धारित किए जाने वाले प्रश्न से संबंधित नहीं है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है। जौहरी लाल के मामले (सुप्रा) में, अंतिम न्यायालय, एक मामले से निपटते समय, जहां आयकर अधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 34(1) (बी) के तहत निर्धारिती के खिलाफ कुछ कार्यवाही की गई थी, और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 34(1) (ए) के तहत, ट्रिब्यूनल द्वारा इसे कायम रखने की अनुमति नहीं दी गई, जो इस प्रकार है: -

“जहां आयकर अधिकारी स्वयं भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 34 (1) (बी) के आधार पर आगे बढ़ता है,

- (7) (1980) 123 आई.टी.आर. 164.
- (8) (1971) 82 1.टी.आर. 824.
- (9) (1980) 123 आई.टी.आर. 200.
- (10) (1978) 112 आई.टी.आर. 995.
- (11) (1973) टी.एल.आर. 113.

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

(1981) 2

और धारा 34 (1) (ए) के आधार पर नहीं, रिकॉर्ड पर सामग्री के अभाव में यह दिखाने के लिए कि आयकर अधिकारी ने अपेक्षित विश्वास का गठन किया था, धारा 34 (1) (ए) के तहत कार्रवाई करने के लिए अपने कारण दर्ज किए) और केंद्रीय बोर्ड या आयुक्त की मंजूरी प्राप्त की, जैसा भी मामला हो, धारा

34 (1) (ए) के तहत आयकर अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को उचित ठहराने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए खुला नहीं है।

धारा 34 (1) (ए) के तहत कार्यवाही वैध रूप से शुरू करने से पहले आयकर अधिकारी द्वारा अपेक्षित विश्वास का गठन एक शर्त है, इस शर्त की पूर्ति महज औपचारिकता नहीं है, यह अनिवार्य है, और ऐसा करने में विफलता उस शर्त को पूरा करने से पूरी कार्यवाही खराब हो जाएगी। इसके अलावा, आवश्यक विश्वास का निर्माण ही एकमात्र आवश्यकता नहीं है, अधिकारी को धारा 34 (1) (ए) के तहत कार्रवाई करने के लिए अपने कारणों को रिकॉर्ड करना होगा और केंद्रीय बोर्ड या आयुक्त की मंजूरी प्राप्त करनी होगी, जैसा भी मामला हो शायद।”

अधिनियम की धारा 263 (1) और धारा 147 (ए) और (बी) के तहत कार्यवाही के बीच अंतर को इंगित करने के लिए राजस्व की ओर से उद्धृत इलेक्ट्रो हाउस के मामले (सुप्रा) के प्राधिकारी से मामले में कोई मदद नहीं मिल रही है। राजस्व का. उक्त मामले में, शामिल प्रश्न आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 33-बी के तहत नोटिस के संबंध में था, जो अधिनियम की धारा 263 के बराबर है, जबकि वर्तमान मामले में ऐसा कोई प्रश्न शामिल नहीं है। उपर्युक्त मामले में, यह आयोजित किया गया था: -

“धारा 34 के विपरीत, आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 338 में आयकर अधिकारी द्वारा पारित आदेश को संशोधित करने के लिए आगे बढ़ने के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने से पहले आयुक्त द्वारा कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्राधिकार- धारा 33-बी के तहत आयुक्त का आगे बढ़ना किसी पूर्व शर्त की पूर्ति पर निर्भर नहीं है। उसे जांच शुरू करने से पहले कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। उसे यह सब अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले करना होगा, न कि उससे पहले जांच शुरू करने का मतलब करदाता को अपनी बात सुनने का अवसर देना और ऐसी जांच करना या कराना है जो वह आवश्यक समझे। इन आवश्यकताओं का कोई लेना-देना नहीं है

आयकर आयुक्त बनाम जगाधरी इलेक्ट्रिक सप्लाय एंड इंडस्ट्रियल कंपनी (जे. वी. गुप्ता, जे.)

आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के साथ. वे प्राकृतिक न्याय के क्षेत्र से संबंधित हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन आदेश की वैधता को प्रभावित कर सकता है लेकिन यह आयुक्त के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है।”

अन्य सभी मामले ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि मूल्यांकन कार्यवाही में अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय दोनों पक्षों को आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार होता है। इस प्रकार, उक्त अधिकारी वर्तमान विवाद को निर्धारित करने में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं।

13. अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत आयुक्त में निहित क्षेत्राधिकार एक विशेष प्रकृति का है या, दूसरे शब्दों में, आयुक्त के पास आयकर अधिकारी के आदेश को संशोधित करने के लिए अधिनियम के तहत विशेष क्षेत्राधिकार है यदि उनका मानना है कि उनके द्वारा पारित कोई भी आदेश इस हद तक गलत था कि यह राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल था। ऐसा करने से पहले, उसे निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देना भी आवश्यक है। यदि अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत उसके द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में निर्धारिती को सुनने के बाद, वह संतुष्ट नहीं है, तो वह आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। बेशक, इस प्रकार पारित आदेश में आयकर अधिकारी के आदेश को गलत मानने का आधार शामिल होगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत माना गया है। इससे व्यथित महसूस करते हुए, निर्धारिती इसके खिलाफ अपील दायर कर सकता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 253 (1) (सी) के तहत प्रदान किया गया है। अपील के ज्ञापन में, निर्धारिती से आयुक्त के आदेश पर हमला करने और उसके आदेश में दिए गए निर्णय के आधार को चुनौती देने की अपेक्षा की जाती है। सुनवाई के समय, यदि निर्धारिती ट्रिब्यूनल को संतुष्ट कर सकता है कि आयुक्त द्वारा आदेश में दिए गए निर्णय के आधार तथ्यों पर गलत हैं या कानून में मान्य नहीं हैं, तो ट्रिब्यूनल के पास अपील स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आयुक्त के आदेश को रद्द करें. ट्रिब्यूनल किसी अन्य आधार पर आयुक्त के आदेश को बरकरार नहीं रख सकता है, जो उसकी राय में, आयुक्त के लिए भी उपलब्ध था। यदि ट्रिब्यूनल को अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत आदेश पारित करने के लिए आयुक्त के पास उपलब्ध आधारों का पता लगाने की अनुमति दी जाती है, तो यह आयुक्त में निहित विशेष क्षेत्राधिकार को साझा करने के समान होगा, जो अधिनियम के तहत जरूरी नहीं है। यह और भी अधिक है, क्योंकि राजस्व को अधिनियम के तहत अपील का कोई अधिकार नहीं दिया गया है

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

(1981)2

अधिनियम की धारा 263(1) के तहत आयुक्त के एक आदेश के विरुद्ध। यदि वह उसके द्वारा दिए गए नोटिस के अनुसरण में निर्धारिती को सुनने के बाद आगे बढ़ता है, तो अधिनियम की धारा 253 (1) (सी) के तहत निर्धारिती द्वारा दायर अपील को उसके खिलाफ अपील के समान नहीं माना जा सकता है। मूल्यांकन कार्यवाही में पारित अपीलीय सहायक आयुक्त का आदेश, जहां दोनों पक्षों को अपील का अधिकार दिया गया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, राजस्व की ओर से उठाया गया तर्क, कि अपील में, ट्रिब्यूनल आयुक्त द्वारा अपने आदेश में लिए गए आधारों के अलावा अन्य आधारों पर अपील किए गए आदेश को बरकरार रख सकता है, तर्कसंगत नहीं है। अधिनियम की धारा 263 के तहत, केवल आयुक्त को ही मामले में आगे बढ़ने के लिए अधिकृत किया गया है और इसलिए, यह उसकी संतुष्टि है जिसके अनुसार वह कानून के अनुसार आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। यदि आदेश पारित होने के समय जो आधार उसके पास उपलब्ध थे, उनका उल्लेख उसके अपील आदेश में नहीं मिलता है, तो यह माना जाएगा कि उसने धारा 263 (1) के तहत किसी भी कार्रवाई के उद्देश्य से उन आधारों को खारिज कर दिया है। अधिनियम। इस स्थिति में, निर्धारिती द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते समय ट्रिब्यूनल उन आधारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, जिन्हें स्वयं आयुक्त ने अपने आदेश का आधार बनाना उचित नहीं समझा।

14. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारी राय में, ट्रिब्यूनल वयस्क भागीदारों की संख्या 10 से 11 तक बढ़ने के तथ्य पर विचार करने में सक्षम नहीं था, जबकि अतिरिक्त आयुक्त ने वास्तव में इस पर भरोसा नहीं किया था। 20 अक्टूबर 1978 के आयकर अधिकारी के आदेश को गलत ठहराते हुए उक्त परिवर्तन। इस प्रकार, उक्त प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध है।

15. लागतों के संबंध में बिना किसी आदेश के संदर्भों का उत्तर तदनुसार दिया जाएगा।

एन.के.एस.

पूरी बेंच

एस.एस. संधावालिया सी.जे. और पी.सी. जैन और जे.एम. टंडन के सामने, जे.जे.

लाल सिंह -याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य आदि, -प्रतिवादी

1980 की सिविल रिट याचिका संख्या 2421

8 अप्रैल 1981

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 162-दण्ड प्रक्रिया संहिता (1974 का द्वितीय) धारा 378-सरकार द्वारा फाइल करने का निर्णय

(अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

रणबीर सिंह अनुवादक